

सामान्य समीक्षा

घटनाक्रमों की समीक्षा

वृहद-आर्थिक सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2006-07 के दौरान सशक्त वृहद-आर्थिक मूलाधारों के साथ जोरदार तीव्र वृद्धि हुई। यही अब तक हुए घटनाक्रमों की विशेषता रही। तथापि मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ वास्तविक चिंताएं उभरी हैं। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में क्रमशः 9 प्रतिशत तथा 9.2 प्रतिशत की वृद्धि आशाओं से कहीं अधिक रही (सारणी 1.1)। हालांकि, कृषि क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति जारी रही, जिसमें हालिया दो वर्षों में 6 प्रतिशत तथा 2.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया तथा सेवाओं ने अपना जोरदार अभिवृद्धि निष्पादन बनाए रखा, औद्योगिक पक्ष में स्थानीय सुधार के सुस्पष्ट चिह्न परिलक्षित हुए हैं (सारणी 1.2)। विनिर्माण क्षेत्र में, विशेष रूप से, हालिया अवधि में उच्चतर अभिवृद्धि प्रवृत्तियां स्थापित हो जाने से देश तथा विदेश दोनों में विश्वास बढ़ा है। समग्र वृहद आर्थिक मूलाधार विशेष रूप से राजकोषीय समेकन तथा भुगतान स्थिति के सशक्त संतुलन की दिशा में ठोस प्रगति होने से मजबूत हैं। निवेश में वृद्धि से संभावनाएं सुस्पष्ट रूप से उत्साहवर्धक हैं।

1.2 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 7 फरवरी 2007 को जारी 2006-07 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान वर्ष में स्थिर कीमतों (1999-2000) पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.2 प्रतिशत है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आरम्भ में फरवरी 2006 में अग्रिम अनुमान चरण पर अनुमानित 8.1 प्रतिशत की वृद्धि को बाद में मई 2006 में संशोधित अनुमान चरण पर संशोधित करके 8.4 प्रतिशत कर दिया गया तथा 31 जनवरी, 2007 को केन्द्रीय सांख्यिकी

संगठन द्वारा जारी त्वरित अनुमानों में इसमें और सुधार कर इसे 9.0 प्रतिशत पर रखा गया।

1.3 हालिया वर्षों में अवलोकित अभिवृद्धि का अनिवर्तन दसवीं योजना (2002-03 से 2006-07) द्वारा लक्षित 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के 9 प्रतिशत के लक्ष्य में प्रतिबिम्बित होता है। दसवीं योजना के पांच वर्षों में 8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि में कमी योजना के प्रथम वर्ष में 3.8 प्रतिशत की निराशजनक वृद्धि तथा बाद के अंतिम चार वर्षों में इसके बढ़कर औसतन 8.6 प्रतिशत हो जाने के कारण है।

1.4 सेवाओं ने 2002-03 तथा 2006-07 के बीच के पिछले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में समग्र औसत वृद्धि के 68.6 प्रतिशत का उच्च योगदान किया। समस्त अवशिष्ट योगदान व्यवहार्यतः उद्योग से प्राप्त हुआ। परिणामतः, 2006-07 में, हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश गिरकर 18.5 प्रतिशत हो गया, उद्योग तथा सेवाओं का अंश सुधर कर क्रमशः 26.4 प्रतिशत तथा 55.1 प्रतिशत हो गया।

1.5 हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सेवाओं की तुलना में उद्योग का निम्नतर अंशदान अंशतः सकल घरेलू उत्पाद में इसके निम्नतर अंश के कारण है तथा इसमें औद्योगिक पुनरूत्थान के चिह्न पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होते। प्रथमतः, औद्योगिक क्षेत्रक की अभिवृद्धि वर्ष 2001-02 में 2.7 प्रतिशत के निम्न स्तर से सुधर कर 2002-03 तथा 2003-04 में क्रमशः 7.1 तथा 7.4 प्रतिशत हो गई तथा अगले दो वर्षों में तेजी से बढ़कर 9.5 प्रतिशत से अधिक होने के पश्चात् 2006-07 में 10.0 प्रतिशत पर पहुंच गई। दूसरे, सेवाओं में सदृश वृद्धि के अनुपात के रूप में उद्योग की वृद्धि जो 1991-92 तथा 1999-2000 के बीच औसतन 78.9 प्रतिशत थी, सुधर कर पिछले सात वर्षों

सारणी 1.1 : मुख्य संकेतक								
मर्दे	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	संपूर्ण मूल्य				पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन			
सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर) (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	2549.4	2855.9	3250.9क्यू	3717.5 ए	12.5	12.0	13.8क्यू	14.4 ए
1999-2000 की कीमतों पर	2222.6	2389.6	2604.5क्यू	2844.0 ए	8.5	7.5	9.0क्यू	9.2 ए
सकल घरेलू उत्पाद-बाजार कीमतों पर (हजार करोड़ रुपए)	2765.5	3126.6	3567.2क्यू	4100.6	12.5	13.1	14.1क्यू	15.0 ए
(वर्तमान कीमतों पर)								
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (उपादान लागत पर) (हजार करोड़ रुपए)								
वर्तमान कीमतों पर	2531.2	2833.6	3225.9क्यू	3693.4 ए	12.6	11.9	13.8क्यू	14.5 ए
1999-2000 की कीमतों पर	2204.7	2367.7	2580.7क्यू	2822.1 ए	8.7	7.4	9.0क्यू	9.4 ए
खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.2	198.4	208.6	209.2 +	22.0	-6.9	5.1	0.3 +
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक(1)	189.0	204.8	221.5	239.0 ^	7.0	8.4	8.2	10.8 ^
उत्पन्न बिजली (बिलियन के.डब्ल्यू.एच. में)	558.3	587.4	617.5	493.1 ^	5.0	5.2	5.1	7.5 ^
शोक मूल्य सूचकांक(2)	180.3	189.5	197.2	209.2 #	4.6	5.1	4.1	6.7 #
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(3)	504	525	551	588 \$	3.5	4.2	5.0	6.9 \$
मुद्रा आपूर्ति (एम ₃)(4) (हजार करोड़ रुपए)	2005.7	2251.4 (2332.7)##	2729.5	3071.7(6)	16.8	12.3	17.0@@	21.1(5)
वर्तमान कीमतों पर आयात (करोड़ रुपए)	3,59,108	5,01,065	6,60,409	5,98,287***	20.8	39.5	31.8	40.6 ^^
(मिलियन अमरीकी डालर)	78,150	1,11,518	1,49,166	1,31,212***	27.3	42.7	33.8	36.3 ^^
वर्तमान कीमतों पर निर्यात (करोड़ रुपए)	2,93,367	3,75,340	4,56,418	4,08,394***	15.0	27.9	21.6	40.6 ^^
(मिलियन अमरीकी डालर)	63,843	83,536	1,03,091	89,489***	21.1	30.8	23.4	36.3 ^^
विदेशी मुद्रा आस्तियां(6) (करोड़ रुपए)	4,66,215	5,93,121	6,47,327	7,64,501*	36.5	27.2	9.1	29.7 *
(मिलियन अमरीकी डालर)	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,73,081*	49.5	26.2	7.0	29.4 *
विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर)(7)	45.95	44.93	44.27	45.48 @	5.3	2.3	1.5	-2.7 @
टिप्पणी : सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े उपादान लागत के अनुसार हैं (नई शृंखला आधार वर्ष 1999-2000) ब्यू-त्वरित अनुमान ए.-अग्रिम अनुमान @ अप्रैल-जनवरी 2006-07 के लिए औसत विनिमय दर @@ वर्ष 2005-06 के दौरान 27 पखवाड़ों के कारण पहली अप्रैल 2005 के तुलनीय आंकड़ों की तुलना में परिकल्पित।								
* जनवरी 2006 के अंत में ** दिसम्बर 2004 के अंत में *** अप्रैल-दिसम्बर 2006 (अनंतिम)								
# 3 फरवरी, 2007 के अनुसार ## 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार								
^ अप्रैल-दिसम्बर, 2006 \$ दिसम्बर, 2006 के अनुसार बकाया अधिशेष + द्वितीय अग्रिम अनुमान 2006-07								
^^ अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में अनंतिम की तुलना में अनंतिम आधार पर								
1. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, (आधार वर्ष 1993-94 = 100)								
2. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार वर्ष 1993-94 = 100)								
3. राजकोषीय वर्ष के अंत में सूचकांक (आधार वर्ष 1982 = 100)								
4. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।								
5. 19 जनवरी, 2006 को वर्षानुवर्ष वृद्धि।								
6. वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया।								
7. प्रतिशत परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की मूल्यवर्धन दर (+)/ह्रास (-) को निर्दिष्ट करता है।								

**सारणी 1.2 : सकल घरेलू उत्पाद में उपादान लागत पर क्षेत्रक वास्तविक वृद्धि दरें
(1999-2000 कीमतों पर)**

मद	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन							
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (क्यू)	2006-07 (ए)	
I. कृषि एवं संबद्ध उद्योग	-0.2	6.3	-7.2	10.0	0.0	6.0	2.7	
II. उद्योग	6.4	2.7	7.1	7.4	9.8	9.6	10.0	
खनन तथा उत्खनन	2.4	1.8	8.8	3.1	7.5	3.6	4.5	
विनिर्माण	7.7	2.5	6.8	6.6	8.7	9.1	11.3	
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	2.1	1.7	4.7	4.8	7.5	5.3	7.7	
निर्माण	6.2	4.0	7.9	12.0	14.1	14.2	9.4	
III. सेवाएं	5.7	7.2	7.4	8.5	9.6	9.8	11.2	
व्यापार, होटल, संवहन तथा संचार	7.3	9.1	9.2	12.1	10.9	10.4	13.0	
वित्तीय, स्थावर सम्पदा तथा व्यापार सेवाएं	4.1	7.3	8.0	5.6	8.7	10.9	11.1	
सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	4.8	4.1	3.9	5.4	7.9	7.7	7.8	
IV. उपादान लागत पर कुल स.घ.उ.	4.4	5.8	3.8	8.5	7.5	9.0	9.2	
पी : अनन्तिम	क्यू : त्वरित अनुमान	ए : अग्रिम अनुमान						
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।								

में 88.7 प्रतिशत पर पहुंच गयी। तीसरे, उद्योग के अंतर्गत, औद्योगिक क्षेत्रक में वृद्धि का आवेग विनिर्माण में पहुंच गया प्रतीत होता है। यदि अन्य दो उप-क्षेत्रकों, नामतः, खनन तथा उत्खनन; एवं बिजली, गैस तथा जलापूर्ति का सापेक्षता निष्पादन निराशाजनक न होता तो औद्योगिक अभिवृद्धि और भी उच्च होती। चौथे, 1951-52 से, उद्योग में वर्ष 2004-05 से पूर्व लगातार तीन वर्ष से अधिक समय के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की सतत् वृद्धि कभी भी दर्शित नहीं हुई। पांचवें, दिसम्बर 2006 तक उपलब्ध मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार विनिर्माण में अक्टूबर के त्रैहारी माह के एकमात्र अपवाद को छोड़कर मार्च 2006 से प्रत्येक माह द्वि-अंकीय दरों पर वृद्धि हो रही है।

1.6 अर्थव्यवस्था में निवेश की दर में तीव्र वृद्धि वर्तमान अभिवृद्धि प्रावस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता है। सामान्यतः एक आशाजनक परिवर्ती होने के कारण निवेश व्यवसाय आशावादिता के उच्चांश को प्रतिबिम्बित करता है। वर्ष 2002-03 में आरम्भ हुए सकल घरेलू पूंजी निर्माण के पुनः प्रवर्तन के पश्चात चार निरंतर वर्षों तक अर्थव्यवस्था में निवेश दर में तीव्र वृद्धि हुई। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने अग्रिम अनुमानों में जारी सकल घरेलू पूंजी निर्माण के वर्ष 2004-05 के लिए 30.1 प्रतिशत के पूर्ववर्ती अनुमान अब बढ़ कर त्वरित अनुमानों में 31.5 प्रतिशत हो गए हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा

जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2005-06 के लिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 33.8 प्रतिशत है। निवेश दर में इस तीव्र वृद्धि ने औद्योगिक निष्पादन को कायम रखा है तथा वृद्धि की संभावना पुनःबलित हुई है।

1.7 सेवाक्षेत्रक की वृद्धि व्यापकाधारित बनी हुई है। सेवा के तीन उप-क्षेत्रकों में, “व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार सेवा” ने चौथे क्रमिक वर्ष के लिए द्वि-अंकीय दरों पर वृद्धि हासिल करते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देना जारी रखा है (सारणी 1.2)। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं, रेल तथा सड़क, दोनों प्रकार के यातायात में प्रभावपूर्ण प्रगति तथा दूरभाष कनेक्शनों, विशेषतः मोबाइलों के विद्यमान स्टॉक में तीव्र वर्धन ने ऐसी वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाई। वित्तीय सेवाओं (जिनमें बैंकिंग, बीमा, स्थावर सम्पदा तथा व्यवसाय सेवाएं शामिल हैं) में वृद्धि वर्ष 2003-04 में गिरकर 5.6 प्रतिशत पर पहुंचने के पश्चात पुनः सुधर कर वर्ष 2004-05 में 8.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-06 में 10.9 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2006-07 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस संवेग को कायम रखा गया है।

1.8 वर्ष 2001-02 से आरम्भ नई सहस्राब्दि के पहले पांच वर्षों में 3.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के पश्चात, वर्ष 2006-07 में विगत वर्ष की तुलना में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात कृषि में केवल

2.7 प्रतिशत की वृद्धि, चिंता का कारण बनी हुई है। निम्न निवेश, उर्वरक के प्रयोग में असंतुलन, बीज प्रतिस्थापन की निम्न दर, विरुपित प्रोत्साहन योजना तथा फसल कटाई के पश्चात निम्न मूल्यवर्धन इस क्षेत्रक के निष्पादन में बाधा बने हुए हैं। इसके निम्न अंश को देखते हुए, समग्र सकल घरेलू उत्पाद पर कृषि की निम्न वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव का प्रक्रियात्मक परिकलन भ्रामक हो सकता है। आधे से अधिक जनसंख्या के सीधे इस क्षेत्रक पर निर्भर होने के कारण निम्न कृषिय वृद्धि के वृद्धि की “समावेशिता” पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में यथा-प्रदर्शित निकृष्ट कृषि निष्पादन दैनंदिन खपत की आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति पक्ष की समस्याएं होने से मूल्य स्थिरता के अनुरक्षण को जटिल बना सकता है। खाद्य प्रसंस्करण के कार्यकलाप में हालिया उछाल तथा फार्म द्वार से उपभोक्ता की प्लेट तक आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण में कुछ मूल कारणों यथा निम्न निवेश, निकृष्ट गुणवत्ता वाले बीजों तथा अल्प फसल-पश्च प्रसंस्करण का निवारण करने की संभाव्यता है।

1.9 घरेलू मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन में कमी आने तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ने से वर्ष 2006-07 में अब तक प्राथमिक वस्तुओं, मुख्यतः खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। गेहूं, दालों, खाद्य तेल, फल तथा सब्जियों एवं मिर्च-मसालों का प्राथमिक वस्तुओं की उच्चतर मुद्रास्फीति दर में प्रमुख योगदान रहा है। 3 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक में समग्र मुद्रास्फीति का 39.4 प्रतिशत का उच्चांश वस्तुओं के प्राथमिक समूह के कारण था। प्राथमिक समूह के अंतर्गत, खनिज उपसमूह ने 18.2 प्रतिशत पर उच्चतम वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति दर्ज की जिसके बाद खाद्य वस्तुओं में यह 12.2 प्रतिशत और खाद्य-भिन्न मदों में 12.0 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक समूह में 15.4 प्रतिशत का उच्च भारांश था। चीनी तथा खाद्य तेलो जैसे विनिर्मित उत्पादों सहित खाद्य मदों का 3 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार 6.7 प्रतिशत की समग्र मुद्रास्फीति में 27.2 प्रतिशत का उच्च योगदान था।

1.10 3.98 प्रतिशत की दर से आरम्भ होते हुए 2006-07 में मुद्रास्फीति दर में सामान्य ऊर्ध्वमुखी रूझान रहा है जिसमें बीच-बीच में गिरावट आई। तथापि, 3 फरवरी 2007 को समाप्त 52 सप्ताह में औसत मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत पर बनी रही। वर्तमान वर्ष में यथा अवलोकित मुद्रास्फीति उछाल 1997-98, 2000-01, 2003-04 तथा 2004-05 में हालिया विगत अवधि में देखा गया था।

1.11 भारतीय अपरिष्कृत तेल समूह (ओमान/दुबई का लगभग 58 प्रतिशत तथा ब्रेंट का 40 प्रतिशत) की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक औसत कीमत वर्ष 2002-04 में लगभग 27-28 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर कर्माधिक स्थिर रहने के पश्चात अगले दो वर्षों में 40 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की दर से बढ़ते हुए 8 अगस्त 2006 को 75.2 अमरीकी डालर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गयी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की वित्त व्यवस्था को टूटने से रोकने के लिए 6 जून 2006 को पेट्रो उत्पादों की खुदरा बिक्री कीमतों में अपरिहार्य ऊर्ध्वमुखी संशोधन हुआ। उपभोक्ताओं, सरकार तथा तेल विपणन कम्पनियों में त्रिपक्षीय भार साझेदारी व्यवस्था में उपभोक्ताओं पर अधिरोपित भार केवल 12.5 प्रतिशत तक सीमित था। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों के कम होने पर, पेट्रोल (मोटर स्पिट) तथा उच्च गति डीजल की घरेलू कीमतों में 30 नवम्बर 2006 से क्रमशः 2 रुपए और 1 रुपए की कमी की गई तथा 16 फरवरी 2007 से पुनः समान राशि की कमी की गई है।

1.12 सरकार ने कीमतों का सन्निकर साप्ताहिक अनुवीक्षण किया तथा वर्धित आयातों, निर्यात प्रतिबंधों एवं राजकोषीय रिआयतों के संयोजन द्वारा गेहूं, दालों, चीनी, तथा खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के उपाय आरम्भ किए। गेहूं में, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ने विदेशों में 55 लाख टन गेहूं के लिए निविदाएं दीं, निजी व्यापारियों को 9 सितम्बर, 2006 से शून्य शुल्क पर गेहूं का आयात करने की अनुमति दी गई; तथा 9 फरवरी, 2006 से निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की प्रभावी वृद्धि की गई तथा बुआई के मौसम से काफी पहले इसकी घोषणा कर दी गई ताकि अतिरिक्त भूमि में गेहूं की बुआई की जाए। दालों का आयात 8 जून 2006 से शून्य शुल्क पर अनुमत किया गया; 22 जून 2006 से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया; तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने विदेशों से उड़द और मूंग की खरीदारी की। गेहूं, चीनी एवं दाल के लिए पण्य वायदा बाजार के विनियमन को कठोर बनाया गया; तथा प्रचुर सुरक्षोपाय के रूप में उड़द तथा तूर में वायदा कारोबार पर 24 जनवरी 2007 से प्रतिबंध लगा दिया गया। खजूर तेल समूह, जो खाद्य तेलों में घरेलू मांग आपूर्ति की आधे से अधिक की कमी की पूर्ति करता है, पर शुल्क में चरणबद्ध तरीके से पहले अगस्त 2006 तथा बाद में जनवरी 2007 में 20-22.5 प्रतिशतांक की कमी की गई। इसके अतिरिक्त, आयात शुल्क निर्धारण के लिए इन तेलों के प्रशुल्क मूल्य

स्थिर कर दिए गए। 22 जनवरी 2007 को पोर्टलैंड सीमेंट, विभिन्न धातुओं तथा मशीनरी मर्चों के लिए शुल्क में और कटौतियों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने के कारण, गेहूं तथा दालों की घरेलू कीमतों को कम करने में उनके शुल्क मुक्त आयात का प्रभाव सीमित रहा। किन्तु ऐसे आयातों ने घरेलू बाजार के अनुशासन में सुधार किया है।

1.13 मुद्रास्फीति, जिसके मूल कारण आपूर्ति पक्ष के कारकों में निहित हैं, के साथ-साथ वर्ष 2005-06 में तथा वर्ष 2006-07 में अब तक मुद्रा एवं ऋण की उत्प्लावक वृद्धि हुई है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2004-05 तथा 2005-06 के बीच 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गई, स्थूल मुद्रा (एम₃) की वृद्धि में तदनुरूपी त्वरण 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 17.0 प्रतिशत हुआ। 20 जनवरी, 2007 को एम₃ की वर्षानुवर्ष वृद्धि 21.1 प्रतिशत थी। वर्ष 2005-06 में औद्योगिक पुनरूत्थान एवं निवेश में आया उछाल सकल बैंक क्रेडिट (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 90 प्रतिशत क्रेडिट को शामिल करने वाले आंकड़ों के अनुसार) में परिलक्षित हुआ तथा उसके द्वारा बरकरार रखा गया, उदाहरणार्थ उद्योग (मझोले एवं बड़े) को 31.6 प्रतिशत पर एवं आवासीय ऋणों के लिए 38.0 प्रतिशत पर। सितम्बर, 2006 में 32.0 प्रतिशत पर सकल बैंक क्रेडिट की वर्षानुवर्ष वृद्धि के संबंध में भी इसे अवलोकित किया गया, यद्यपि यह वृद्धि वर्ष 2005-06 में 37.1 प्रतिशत से कुछ कम थी। एक ओर विकास के लिए ऋण को सुकर बनाने एवं दूसरी ओर मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए नकदी को नियंत्रित करने की दोहरी आवश्यकता में सामंजस्य के लिए नीतियों का अंशांकन एक चुनौती बना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैयक्तिक ऋणों, पूंजी बाजार देनदारियों, 20 लाख रुपए से अधिक के आवासीय गृह निर्माण, एवं वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति ऋणों की तीव्र वृद्धि पर इन श्रेणियों के अन्तर्गत मानक अग्रिमों के लिए आवश्यकताओं के लिए प्रावधान को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर अप्रैल, 2006 में दुगुने से भी ज्यादा 1.0 प्रतिशत करके रोक लगा दी है। साथ ही साथ, इसने वाणिज्यिक अचल सम्पत्ति की देनदारियों पर जोखिम भार को 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया है।

1.14 भारतीय रिजर्व बैंक के पास केन्द्र सरकार के अधिशेष को बाजार में लगाने और व्यवस्थित स्थितियां बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर की गई दखल कार्रवाई के परिणामस्वरूप सितम्बर 2006 की आरंभिक अवधि तक नकदी स्थितियां काफी हद

तक सुगम रहीं। वर्ष 2006-07 के दौरान, 8 सितम्बर, 2006 तक भारतीय रिजर्व बैंक को नकदी समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो के लिए कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी एवं रिवर्स-रेपो के अंतर्गत निधियों के निरंतर प्रवाह ने सुगम नकदी स्थिति को इंगित किया। वर्ष 2005-06 में 29 अप्रैल तथा 26 अक्टूबर, 2005 तथा 24 जनवरी, 2006 को प्रत्येक अवसर पर रिवर्स-रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि की गई जिससे यह 5.50 प्रतिशत पर पहुंच गई। वर्ष 2006-07 में इसमें पुनः 9 जून एवं 25 जुलाई, 2006 को प्रत्येक बार 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि की गई। त्यौहारों का समय प्रारम्भ होने एवं अग्रिम कर भुगतान के कारण बहिर्प्रवाहों के साथ साथ उच्च ऋण विस्तार के कारण कुछ कठिनाई हुई। सितम्बर माह के मध्य से अक्टूबर, 2006 के दौरान, जब भारतीय रिजर्व बैंक को रिवर्स-रेपो के जारी रहते रेपो सुविधा के माध्यम से कुछ बैंकों की नकदी को समायोजित करना था, निवल संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणाली से नकदी को समाहित किया।

1.15 अगस्त 2006 के आरंभ से ही वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति लगातार 5 प्रतिशत से अधिक रहने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 अक्टूबर, 2006 को स्फीतिकारी संभावनाओं को खत्म करने और ऋण लेने की मात्रा को निर्धारित 20.0 प्रतिशत की वांछित वृद्धि दर पर ही सीमित करने के लिए उपायों की घोषणा की। विगत चार बार से भिन्न, जब रेपो तथा रिवर्स रेपो दरों को हर बार 25 आधार बिंदु बढ़ाकर उनके विस्तार को 100 आधार बिंदु पर सतत् रखा गया था, 31 अक्टूबर, 2006 को केवल रेपो दर में 25 आधार बिंदु की वृद्धि की गई। 31 जनवरी, 2007 को इसी नीति की पुनरावृत्ति द्वारा रिवर्स रेपो दर की तुलना में 150 आधार बिंदु के विस्तार के साथ रेपो दर 7.50 प्रतिशत पर पहुंच गई। चूंकि जमाराशियों में ऋण की अपेक्षा निम्नतर दर पर वृद्धि हो रही है, उच्चतर रेपो दर ने बैंकों को नकदी समायोजन की उच्चतर कीमत के संकेत दिए जो उन्हें ऋण के अति विस्तार के मामले में अदा करनी पड़ेगी।

1.16 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 23 दिसम्बर, 2006 (5.25 प्रतिशत) और 6 जनवरी, 2007 (5.50 प्रतिशत) को प्रत्येक बार 25 आधार बिन्दु तक बढ़ाया गया। 17 फरवरी, को जहां सी आर आर में 25 आधार बिंदु की और वृद्धि की गई, वहीं 3 मार्च, 2007 को इसी प्रकार 25 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की जाएगी।

1.17 हाल के वर्षों में देखी गई आरक्षित मुद्रा (एम₃) के सापेक्ष एम₃ में निरन्तर अधिक तीव्र वृद्धि 2005-06 और

2006-07 में अब तक बनी रही जिसमें मुद्रा गुणक $\left(\frac{एम_3}{एम_0}\right)$ निरन्तर रूप से मार्च 2002 के अंत में 4.43 से मार्च 2005 के अंत में 4.60, मार्च 2006 के अंत में 4.76 और 19 जनवरी, 2007 को और बढ़कर 4.79 हो गया। मुद्रा-गुणक में वृद्धि 2005-06 के दौरान 17.2 प्रतिशत और 19 जनवरी, 2007 को 20.0 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ-साथ ही बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप $एम_3$ की तीव्र वृद्धि हुई।

1.18 आरक्षित मुद्रा की तीव्र वृद्धि का कारण भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी परिसम्पत्तियां थी। इंडिया मिलेनियम जमाराशियों के मोचन के बाद भी, भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी परिसम्पत्तियों में 60,193 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और इसने 2005-06 के दौरान $एम_0$ की 17.2 प्रतिशत वृद्धि में 12.3 प्रतिशतांक का अंशदान किया। मार्च, 2006 के अन्त और 19 जनवरी, 2007 के बीच निवल विदेशी परिसम्पत्तियों की तदनुरूपी वृद्धि 114,338 करोड़ रुपए थी। व्यवस्था में नकदी निधि पर बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के प्रचालनों द्वारा ध्यान दिया जाता रहा। इस योजना के अधीन बकाया शेष 31 मार्च, 2006 को 29,062 करोड़ रुपए ($एम_3$ का 1.0 प्रतिशत) से 25 अगस्त, 2006 को 42,364 करोड़ रुपए ($एम_3$ का 1.5 प्रतिशत) के उच्च स्तर तक बढ़ने के बाद घटना शुरू हुए और 19 जनवरी, 2007 को 40,491 करोड़ रुपए ($एम_3$ का 1.3 प्रतिशत) पर पहुंच गए।

1.19 नकदी निधि और मुद्रास्फीति की स्थिति में परिवर्तन 2005-06 और 2006-07 में अब तक ब्याज दरों में निरन्तर बढ़ोत्तरी में परिलक्षित होता है। ऋण की उच्च मांग के अनुरूप जमाराशि में पर्याप्त वृद्धि न होने से ऋण-जमा अनुपात में निरन्तर वृद्धि और ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी हुई। उदाहरणार्थ 10-वर्षीय अवशिष्ट परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर आय जो 2005-06 के दौरान 84 आधार बिन्दु से बढ़कर मार्च, 2006 के अंत में 7.53 प्रतिशत पर जा पहुंची थी, 14 फरवरी, 2007 को और बढ़कर 8.08 प्रतिशत हो गई थी। मांग मुद्रा दरों में घट-बढ़ भी इसी प्रकार की तस्वीर प्रस्तुत करती है। दरों का बढ़ना आय वक्र के लघुतर सिरे पर अधिक मुखर था, जो अल्पावधि में केवल मुद्रास्फीति के बारे में चिन्ताएं दर्शाता है।

1.20 भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी परिसम्पत्तियों में तीव्र वृद्धि ने भुगतान संतुलन के माध्यम से विदेशी मुद्रा

आरक्षित निधियों के तीव्र प्रवाह को परिलक्षित किया। भुगतान संतुलन के माध्यम से प्रारक्षित भण्डार अनुवृद्धि 2005-06 में 15.1 बिलियन अमरीकी डालर और 2006-07 के पहले छह महीनों के दौरान 8.6 बिलियन अमरीकी डालर थी। अन्य प्रमुख करेंसियों की तुलना में अमरीकी डालर के अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप जहां 2005-06 में वर्तमान वर्ष की पहली छमाही में 5.0 बिलियन अमरीकी डालर की मूल्यांकन क्षति हुई, वहीं अमरीकी डालर के कमजोर होने से इतनी ही राशि का मूल्यांकन लाभ हुआ। स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आरक्षित ट्रांश स्थिति और मूल्यांकन परिवर्तनों को शामिल करके, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार मार्च, 2005 के अंत में 141.5 बिलियन अमरीकी डालर, मार्च, 2006 के अंत में 151.6 मिलियन डालर, सितम्बर, 2006 के अंत में 165.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। 9 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार ये प्रारक्षित भंडार 185.1 बिलियन अमरीकी डालर थे।

1.21 2005-06 में और 2006-07 की पहली छमाही में पूंजी प्रवाहों से क्रमशः 9.2 बिलियन अमरीकी डालर और 11.7 बिलियन अमरीकी डालर के भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटे की पूर्ति कर दी तथा यह प्रारक्षित भंडार अनुवृद्धि में परिणामी हुई। चालू खाता घाटे ने पिछले दो वर्षों में बढ़े और बढ़ते हुए व्यापार घाटे को परिलक्षित किया। निर्यात तेजी से बढ़े लेकिन आयात उससे भी अधिक तेजी से बढ़े, जो आंशिक रूप से इस समय निवेश में आए उछाल तथा उच्च अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम मूल्य को परिलक्षित करता है। 2005-06 में आयात (अमरीकी डालर में और सीमाशुल्क आधारित) 33.8 प्रतिशत बढ़े। वर्तमान वर्ष के पहले नौ महीनों में, आयातों में 36.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेट्रोलियम आयात जहां तेजी से बढ़ना जारी रहे, वहीं तेल-भिन्न आयात में वृद्धि वर्तमान वर्ष के पहले नौ महीनों में साधारण गिरावट के साथ 18.7 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतया उच्च सर्राफा मूल्यों के कारण था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के पहले कुछ महीनों में सोने और चांदी के आयात में गिरावट आई। पेट्रोलियम तेल-ल्यूब्रीकेंट्स-भिन्न कारोबार संतुलन, 2003-04 तक कुछ समय के लिए अधिशेष में रहने के बाद, 2004-05 से ऋणात्मक हो गया है।

1.22 भारत के निर्यात (अमरीकी डालर में और सीमाशुल्क आधारित) 2002-03 के बाद से 20 प्रतिशत से अधिक की उच्च दर से बढ़ रहे हैं। 2005-06 के दौरान 23.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत के निर्यात ने 100 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर को पार कर लिया। 2006-07 के दौरान, एक धीमी शुरुआत के बाद, निर्यातों

ने तेजी पकड़ी और यह पहले नौ महीनों में अनुमानित 36.3 प्रतिशत बढ़कर 89.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गए। निर्यातों में तेजी विनिर्माण क्षेत्र में पुनः आई तेजी और प्रमुख कारोबारी हिस्सेदारों से निरन्तर मांग का परिणाम थी।

1.23 कुल मिलाकर, वैदेशिक परिदृश्य अवलम्बकारी बना रहा जिसमें अदृश्य खाता सुदृढ़ और स्थिर था तथा पूंजी प्रवाहों ने मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि हुई, के कारण उत्पन्न चालू खाता घाटे के साधारण स्तरों को अवांछित रूप से वित्त पोषित किया। अदृश्य प्राप्तियों (निवल), जिसमें गैर-उपादान सेवाएं (जैसे यात्रा, परिवहन, सॉफ्टवेयर सेवाएं और कारोबार सेवाएं), निवेश से प्राप्त आय, और अन्तरण सम्मिलित हैं, की बड़ी सीमा तक व्यापार घाटे की क्षतिपूर्ति करने की प्रवृत्ति 2005-06 से लेकर 2006-07 की पहली छमाही तक बनी रही और इसके परिणामस्वरूप 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत का साधारण चालू खाता घाटा हुआ।

1.24 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद के 11.5 प्रतिशत पर अदृश्य (प्राप्तियों) ने 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.4 प्रतिशत के मामूली स्तर से सुदृढ़ वृद्धि प्रदर्शित की। हालिया दो वर्षों में, विशेषकर सॉफ्टवेयर और व्यवसाय सेवाओं में तेजी दिखाई दी। इसके साथ ही 2005-06 में संघट्ट में 6.2 प्रतिशत पर अदृश्य अदायगियों में वृद्धि हुई, यद्यपि यह न्यूनतर स्तरों पर और कुछ सीमा तक असमान थी, और इसमें भी पिछले दो वर्षों में तेजी देखी गई। प्राप्तियों के अधीन, पर्यटन से अर्जन के 2006 में 6.6 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने का अनुमान है। जनवरी, 2007 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने एक पर्यटन गंतव्य के रूप में दक्षिण एशिया के आविर्भाव का उल्लेख किया है जहां वर्ष 2005-06 में पर्यटकों के आगमन में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो वैश्विक अभिवृद्धि की तुलना में दोगुने में अधिक है। इसके अतिरिक्त, इसमें उल्लेख किया गया है कि दक्षिण एशिया के पर्यटकों की अभिवृद्धि को भारत द्वारा बढ़ावा मिला जो उप-क्षेत्र में आने वाले आधे से अधिक पर्यटकों के लिए उत्तरदायी गंतव्य स्थल है।

1.25 भारत में पूंजीगत प्रवाह सुदृढ़ बने रहे। तथापि प्रवाहों की मात्रा में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में उतार-चढ़ाव आता रहा। 2002-05 की तीन साल की अवधि में बड़ी मात्रा में 'अन्य प्रवाह' (विलम्बित निर्यात प्राप्तियां और अन्य) थे जो निवल पूंजी प्रवाहों का काफी बड़ा हिस्सा थे। पूर्ववर्ती दो वर्षों में बहिर्प्रवाह रहने के बाद-दो प्रमुख ऋण सृजक

प्रवाहों-वैदेशिक सहायता और विदेशी वाणिज्यिक उधार, में 2004-05 में तेजी आई। कुल पूंजी प्रवाहों के अनुपात के रूप में ये ऋण प्रवाह 2004-05 में 25 प्रतिशत और 2005-06 में 18 प्रतिशत थे। पूंजी प्रवाहों के अनुपात के रूप में विदेशी निवेश 2005-06 में समाप्त होने वाले पिछले चार वर्षों में 39.1 प्रतिशत से 79.3 प्रतिशत की सीमा में रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों (निवल) में तीव्र वृद्धि हुई, जिसमें इन प्रवाहों का तीन-चौथाई इक्विटी के रूप में था। 2005-06 में 27.4 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर, 2006 में 98.4 प्रतिशत की वृद्धि दर थी। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत सरल बहिर्प्रवाहों के बाद भी था, जिसमें घरेलू निगमित निकायों विदेशों में अधिग्रहण के जरिए, प्रौद्योगिकी और बाह्य पहुंच लाभों का फायदा उठाने का प्रयास किया। विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाह, जो पोर्टफोलियो प्रवाहों का प्रमुख प्रकार है, 2005-06 तक तेज रहने के बाद 2006-07 की पहली छमाही में निवल बहिर्प्रवाहों में बदल गए। विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाहों के वर्तमान वर्ष की दूसरी छमाही में पुनः सकारात्मक होने की सूचना है।

1.26 भुगतान संतुलन के माध्यम से विदेशी निवेश प्रवाहों में तेजी ने आंशिक रूप में घरेलू पूंजी बाजारों में तेजी की प्रवृत्तियों को परिलक्षित किया। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अग्रणी स्टॉक-सूचकांक, बीएसई-सेनसेक्स में 14 जून, 2006 को 8,929 के निम्न स्तर से 9 फरवरी, 2007 को 14,724 के सर्वोच्च अन्तः दिवसीय उच्च स्तर तक उछाल आया। केवल 26 कारोबारी सत्रों में 13,000 के अंक से 14,000 अंक तक की छलांग 1000 अंकों की तीव्रतम छलांग है। 12 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के 91.5 प्रतिशत के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की तुलना सकारात्मक रूप से न केवल उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के साथ, बल्कि जापान (96 प्रतिशत) और दक्षिण कोरिया (94.1 प्रतिशत) के साथ भी की जा सकती है। वृहद खुदरा भागीदारी से बाजार की लघु-संरचना की सुदृढ़ता बनी रही।

1.27 सकारात्मक प्रवृत्तियां प्राथमिक बाजार के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों जैसे अधिकांश संकेतकों में भी दृष्टिगोचर थीं। सकल संग्रहण, विशेष रूप से आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आई पी ओ) और गैर-सरकारी नियोजनों के माध्यम से कलैंडर वर्ष 2006 में 30.5 प्रतिशत तक बढ़कर 161,769 करोड़ रुपए हो गया जिसमें प्रतिमाह औसतन लगभग 6 आई पी ओ आए। म्युचुअल फंडों द्वारा संसाधनों का निवल संग्रहण 2005 में 25,425 करोड़ रुपए से चौगुने से अधिक बढ़कर 2006 में 1,04,950 करोड़ रुपए हो गया। म्युचुअल

फंडों द्वारा संग्रहण में तीव्र वृद्धि आय/ऋण उन्मुखी स्कीमों तथा ग्रोथ/इक्विटी उन्मुखी स्कीमों दोनों के अंतर्गत तीव्र अन्तर्प्रवाहों के कारण थी। सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों के लिए 2004 में ऋणात्मक अंतर्प्रवाह 2005 में धनात्मक हो गए और 2006 में इनमें तेजी आई। बाजार प्रवृत्तियों के अन्य संकेतक जैसे कि इक्विटी रिटर्न और मूल्य/आय अनुपात भी सुदृढ़ और वृद्धि में सहायक बने रहे।

1.28 पूंजी बाजारों का उत्साहजनक रुख, जो अर्थव्यवस्था की उन्नत विकास की संभावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है, आंशिक रूप से आधारभूत ढांचा क्षेत्र में की गई सतत प्रगति का भी परिणाम है। छह महत्वपूर्ण उद्योगों-विद्युत, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट-जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 27 प्रतिशत का भारांश था-में अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में 5.5 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। परिवहन और संचार के क्षेत्र में, रेलवे ने वर्तमान वर्ष के पहले नौ महीनों में लगभग द्वि-अंकीय की वृद्धि बनाए रखी। तथापि प्रमुख समुद्री पत्तों (निर्यात और आयात दोनों) तथा हवाई अड्डों (निर्यात) में ढुलाई किए गए माल में गिरावट देखी गई। हाल के महीनों में नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस की खोज का समाचार देश की हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आयात पर कम निर्भरता की तलाश की दिशा में एक उत्साहवर्धक घटनाक्रम है।

1.29 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसररचना के लिए निवेश की अपेक्षाएं अनुमानतः 320 बिलियन अमरीकी डालर की होगी। जबकि इन संसाधनों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र से आयेगा, शेष भाग निजी क्षेत्र और/अथवा सरकारी निजी भागीदारी से प्राप्त करना होगा। सरकारी निजी भागीदारी के संभाव्य लाभ हैं: कम लागत, उच्चतर उत्पादकता, त्वरित परिदाय, स्पष्ट ग्राहक संकेन्द्रण सामाजिक सेवाओं में वृद्धि और प्रयोक्ता शुल्कों की वसूली। इसके अतिरिक्त, सरकारी निजी भागीदारी द्वारा पैसे की कीमत के साथ लाए जाने वाले संसाधनों की वृद्धि संवेदी बनी हुई है। अनुमोदित की जा चुकी अथवा विचाराधीन परियोजनाओं की संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस रास्ते के माध्यम से लगभग छह गुणा शक्ति प्राप्त की जा सकेगी।

1.30 अत्यधिक जरूरतमंद अवसररचना का विकास करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का निवेश करने की सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता महत्वपूर्ण रूप से राजकोषीय गुंजाइश सृजन

करने पर निर्भर करती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जो एक संस्थागत ढांचे में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को कायम करने के नीतिगत संकल्प का चरम बिन्दु है, ने ऐसी राजकोषीय गुंजाइश सृजित करने की दृष्टि से अच्छे परिणाम दिए हैं। वर्ष 2005-06 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत तक कम हो गया है और वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.8 प्रतिशत तक होने का बजटीय प्रावधान किया गया। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के पंचाट जो केन्द्र और राज्य दोनों के सार्वजनिक वित्त का पुनर्गठन करने के लिए अशांकित किया गया था को क्रियान्वित करने के साथ इस प्रक्रिया में तेजी आ गयी। चालू वर्ष में सघन के अनुपात के रूप में राज्यों का बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा अधिदेशित 3 प्रतिशत से भी कम हो गया है जो निर्धारित समय से दो वर्ष आगे है और केवल मामूली राजस्व घाटा ही शेष है जिसे समाप्त करना है। अन्य बातों के साथ-साथ टीएफसी पंचाट के क्रियान्वयन और वर्ष 2005-06 में राजकोषीय समेकन में विराम के कारण, केन्द्र के घाटा संकेतकों में गिरावट इसके संसाधनों पर दबावों के कारण अपेक्षाकृत कम रही है। राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के उद्देश्यों से समझौता किए बिना वर्ष 2006-07 में राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करना एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिद्धता को दर्शाता है।

1.31 भारत में चल रही राजकोषीय समेकन प्रक्रिया अधिकांश अन्य देशों में व्यय संकुचन नीति के विपरीत अनिवार्य रूप से राजस्व अभिप्रेरित रही है और इसमें परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही व्यय का पुनः प्राथमिकता निर्धारण शामिल है। केन्द्र का कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निरन्तर बढ़कर 2002-03 में 8.8 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 10.3 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2006-07 की बजटीय व्यवस्था में 11.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2005-06 में कारपोरेट आयकर और वैयक्तिक आयकर में क्रमशः 20.3 प्रतिशत और 22.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में क्रमशः 55.2 प्रतिशत और 30.3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। प्रत्यक्ष कर राजस्व में तीव्र वृद्धि होने से वर्ष 2006-07 (ब०अ०) में कुल राजस्व में इसका हिस्सा 47.6 प्रतिशत होने में सहायता मिली। राजस्व और राजकोषीय घाटों में कमी में राजस्व उत्प्लावक वृद्धि में व्यय संयोजन में परिवर्तन अनुपूरक रहा। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केन्द्र का कुल व्यय

वर्ष 2002-03 में 16.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 14.1 प्रतिशत हो गया, समान आधार पर आयोजना को बजटीय सहायता (राज्यों की मध्यस्थता के बिना ऋणों सहित) 1,11,470 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,72,500 करोड़ रुपए हो गई। चालू राजस्व से शेष, जो वर्ष 2003-04 तक ऋणात्मक रहा था, 2004-05 में धनात्मक हो गया तथा वर्ष 2005-06 में सुदृढ़ होकर 22,332 करोड़ रुपए हो गया है। कुल व्यय में आयोजना-भिन्न व्यय के 2002-03 में 73.0 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 (बजट अनुमान) में 69.4 प्रतिशत हो जाने से व्यय के पुनः पूर्विकता निर्धारण के सुस्पष्ट संकेत मिले हैं। सरकार के उधारों के निम्नतर स्तरों के कारण निजी बचतों पर सार्वजनिक क्षेत्रक ड्राफ्ट में कमी आई है।

उपभोग, बचत और निवेश

1.32 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतों में वृद्धि की प्रवृत्ति, जो 2001-02 से दिखायी

दी थी, जारी रहने से बचतों का अनुपात वर्ष 2002-03 में 26.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003-04 में 29.7 प्रतिशत, 2004-05 में 31.1 प्रतिशत और 2005-06 में 32.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 1.3)। वर्ष 2005-06 में बचत दर में वृद्धि होने के तीन घटकों में से दो घटक हैं: निजी कारपोरेट और घरेलू क्षेत्र। इनसे सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में यह वृद्धि क्रमशः 1.0 प्रतिशत अंक और 0.7 प्रतिशत अंकों की हुई है। तृतीय घटक अर्थात्: सार्वजनिक बचत हैं जिसमें 0.4 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है, और इस कारण सम्पूर्ण बचत दर में ऋणात्मक योगदान रहा। तथापि, हाल के वर्षों की एक अच्छी बात यह रही कि सार्वजनिक क्षेत्र में बचत जो 2002-03 तक ऋणात्मक थी लगातार तीसरे वर्ष 2005-06 में सकारात्मक रही। वर्ष 2005-06 (बजट अनुमान) में 71,262 करोड़ रुपये की धनात्मक बचत का श्रेय ज्यादातर गैर-विभागीय और विभागीय उद्यमों की उच्चतर बचतों को जाता है।

सारणी 1.3 : बचत और निवेश (आधार : 1999-2000)

(नवीन शृंखला आधार वर्ष 1999-2000)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (पी)	2004-05 (क्यू)	
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)							
सकल घरेलू बचतें	24.8	23.4	23.5	26.4	29.7	31.1	32.4
क) सरकारी	-0.8	-1.9	-2.0	-0.6	1.2	2.4	2.0
ख) निजी	25.6	25.3	25.5	27.0	28.5	28.7	30.4
i) पारिवारिक	21.1	21.0	21.8	22.7	23.8	21.6	22.3
वित्तीय	10.6	10.2	10.8	10.3	11.3	10.2	11.7
वास्तविक	10.5	10.8	10.9	12.4	12.4	11.4	10.7
ii) निजी कारपोरेट	4.5	4.3	3.7	4.2	4.7	7.1	8.1
सकल घरेलू निवेश*	25.9	24.0	22.9	25.2	28.0	31.5	33.8
सरकारी	7.4	6.9	6.9	6.1	6.3	7.1	7.4
निजी	17.9	16.5	16.3	18.4	19.4	21.3	23.6
बहुमूल्य वस्तुएं	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2
सकल नियत पूंजी निर्माण	23.4	22.8	23.0	23.8	24.8	26.3	28.1
स्टॉक में परिवर्तन	1.9	0.6	0.2	0.7	0.8	2.0	2.9
बहुमूल्य वस्तुएं	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2
बचत-निवेश में अंतर @	-1.1	-0.6	0.6	1.2	1.6	-0.4	-1.3
सरकारी	-8.2	-8.8	-8.9	-6.6	-5.2	-4.7	-5.4
निजी	7.7	8.8	9.2	8.6	9.2	7.4	6.9
टिप्पणी :	सकल घरेलू निवेश, सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) का द्योतक है और भूल चूक के लिए समायोजित है। आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।						
*	: भूल-चूक के लिए समायोजित है।						
@	: बचत और निवेश की दरों के बीच अंतर का द्योतक है।						
जी.एफ.सी.एफ.	: सकल नियत पूंजी निर्माण						
क्यू	: त्वरित अनुमान						
स्रोत	: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन						

1.33 भारतीय अर्थव्यवस्था के बचत परिदृश्य में एक नाटकीय घटक यह रहा है कि लगातार चार वर्षों में भी निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत दर में तेजी से अभिवृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के निजी कारपोरेट बचतों के वर्ष 2004-05 के पूर्व के त्वरित अनुमान को सीएसओ द्वारा जारी अनन्तिम अनुमानों में 7.1 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। त्वरित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2005-06 में बचत दर 8.1 प्रतिशत हुई। निजी कारपोरेट क्षेत्र ने ऐसी प्रतिधारित प्राप्तियों अथवा बचतों से चल रही दीर्घ केपेक्स साइकिल में अपने निवेश का एक बड़ा भाग लगाया।

1.34 वर्ष 2004-05 और 2005-06 के मध्य सकल घरेलू बचत दर में 1.3 प्रतिशतता बिन्दुओं की हुई वृद्धि में, 0.7 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि घरेलू क्षेत्र की रही है। भारतीय परिवारों की निवेश सूची प्रवृत्ति पर निम्नलिखित दो ताकतें एक साथ काम कर रही हैं- बैंकों से आवास ऋण लेकर आवासीय भवनों का अत्यधिक निर्माण, तथा घरेलू वित्तीय बाजारों का क्रमिक रूप से परिपक्व होना पहले की प्रवृत्ति जहां वास्तविक रूप में घरेलू बचतों को बढ़ाने की रही है, वहीं दूसरे की प्रवृत्ति उच्च वित्तीय बचतों के लिए प्रोत्साहन देने की रही है। वर्ष 2005-06 में समाप्त तीन वर्षों में पारिवारिक पोर्टफोलियो में दृष्टका परिवर्तन रहा। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में वास्तविक बचतों में काफी गिरावट आयी, ये 2003-04 में 12.4 प्रतिशत थी जो 2005-06 में कम होकर 10.7 प्रतिशत रह गयी। दूसरी ओर, वित्तीय बचत, जो 2003-04 और 2004-05 के मध्य 11.3 प्रतिशत से घटकर 10.2 प्रतिशत हो गयी थी, 2005-06 में काफी बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गयी।

1.35 बचत दर में वृद्धि होने से, अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर प्राप्त किए जाने तथा निर्भरता अनुपात गिरने की संभावना होती है। 15-64 वर्ष के कार्यशील आयु वर्ग की आबादी के अनुपात के 2006 में 62.9 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 68.4 प्रतिशत हो जाने के परिणामस्वरूप, उच्च बचत-दर के रूप में जनसांख्यिकीय लाभ के बने रहने की संभावना है। जैसे ही बचत दर बढ़ी है, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मौजूदा कीमतों पर निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय में विशेषकर 2001-02 से गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी है। सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात में पीएफसीई वर्ष 2002-03 के 63.1 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2003-04 में 62.1 प्रतिशत, 2004-05 में 60.0 प्रतिशत और 2005-06

में 58.7 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट विभिन्न जिन्स समूह के हिस्सों के संदर्भ में उपभोग बास्केट में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ रही। निजी अंतिम उपभोग व्यय में खाद्य, पेय-पदार्थों और तम्बाकू का हिस्सा वर्ष 2002-03 के 43.3 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2005-06 में 39.4 प्रतिशत रह गया। पीएफसीई के अनुपात के रूप में अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण मदों, जैसे, परिवहन और संचार में वृद्धि वर्ष 2002-03 में 15.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 19.1 प्रतिशत हो गयी।

1.36 वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, वर्ष 2002-03 के 11.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2004-05 में 11.0 प्रतिशत रह जाने के बाद, बढ़कर वर्ष 2005-06 में सं.घ.उ. का 11.5 प्रतिशत हो गया है।

1.37 वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के बीच सकल घरेलू बचत की दर में वृद्धि के साथ, सकल घरेलू पूंजी निर्माण अथवा निवेश की दर सं.घ.उ. के 28 प्रतिशत से बढ़कर सं.घ.उ. के रूप में 31.5 प्रतिशत हो गयी थी जिससे वर्ष 2004-05 में बचत निवेश अंतर अथवा चालू खाता घाटा सं.घ.उ. का 0.4 प्रतिशत है (सारणी 1.3)। त्वरित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) में सकल घरेलू उत्पाद की 33.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे भुगतान संतुलन चालू खाते की जटिलताओं के साथ बचत-निवेश अंतर बढ़ कर सं.घ.उ. का 1.4 प्रतिशत हो गया।

1.38 स्थिर कीमतों (आधार: 1999-2000) पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू उत्पाद के समानुपातिक रूप में (सारणी 1.4) वर्तमान मूल्यों (सारणी 1.3) पर तदनुसारी अनुपात की अपेक्षा निरन्तर कम है। यह भिन्नता सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप में विनिर्माण में उत्पादन प्रक्रियाओं के बढ़ते हुए प्रौद्योगिकीय अत्याधुनिकीकरण से सामान्य मूल्य स्तर के अनुपात में पूंजीगत सामान की कीमतों में भारी वृद्धि को प्रतिबिम्बित करती है। परन्तु, भारांशों के रूप में स्थिर या वर्तमान मूल्यों में कुछ भी चुना जाए तो, वर्षानुवर्ष परिवर्तन की दिशा अपरिवर्तित रहती है।

1.39 सकल घरेलू पूंजी निर्माण के दो संघटकों नामतः सकल नियत पूंजी निर्माण तथा स्टॉकों में परिवर्तन में, सकल नियत पूंजी निर्माण (जिसमें संयंत्र तथ्य मशीनरी जैसी मदे शामिल हैं) का सकल घरेलू पूंजी निर्माण के

सारणी 1.4 : वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण
(1999-2000 की बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(क्यू)
जी.डी.सी.एफ. *	25.9	23.8	22.2	25.0	27.4	30.2	32.2
सरकारी	7.4	6.9	6.8	6.1	6.0	6.5	6.9
निजी	17.9	16.3	15.8	18.1	19.1	20.6	22.6
निजी कार्पोरेट क्षेत्र	7.4	5.6	5.2	5.8	6.7	9.5	12.2
पारिवारिक क्षेत्र	10.5	10.6	10.6	12.3	12.4	11.1	10.3
बहुमूल्य वस्तुएं	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2
जी.एफ.सी.एफ.	23.4	22.5	22.4	23.5	24.5	25.3	26.7
सरकारी	6.6	6.5	6.4	6.2	6.4	6.2	6.5
निजी	16.8	16.1	16.0	17.2	18.1	19.0	20.2
स्टॉक में परिवर्तन	1.9	0.6	0.1	0.7	0.6	1.8	2.8
सरकारी	0.8	0.4	0.4	-0.2	-0.3	0.3	0.4
निजी	1.1	0.2	-0.2	0.9	0.9	1.5	2.4
बहुमूल्य वस्तुएं	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2
टिप्पणी:							
जीडीसीएफ: सकल घरेलू पूंजी निर्माण;							
जीएफसीएफ: सकल नियत पूंजी निर्माण;							
आंकड़े पूर्णांक कर दिए जाने के कारण संभवतः योग से मेल न खाएं।							
* भूल-चूक के लिए समायोजित							
क्यू : त्वरित							
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन							

योगदान 2003-04 तथा 2004-05 के बीच स्टॉकों के परिवर्तनों के तदनुसूची योगदान से निम्नतर था। हालांकि वर्ष 2004-05 और 2005-06 के बीच सकल घरेलू पूंजी निर्माण की वृद्धि के योगदान के सन्दर्भ में सकल नियत पूंजी निर्माण स्टॉकों में परिवर्तन से लगातार पिछड़ी हुई थी, तो भी दोनों के योगदान में अन्तर कम हुआ। यह नियत पूंजीगत संरचना, विशेष तौर पर निजी क्षेत्र में, के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता सृजन के लिए हाल के नये निवेश को दर्शाता है।

1.40 मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में, पूर्वी एशियाई देशों की उनके उच्च-वृद्धि चरण के दौरान अथवा हाल के वर्षों में चीन से भिन्न, भारत में सुधारों के बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अधिकतर अंतिम निजी खपत अथवा पी एफ सी ई वृद्धि द्वारा संचालित थी। पी एफ सी ई का योगदान वर्ष 2001-02 तक प्रत्येक वर्ष की वृद्धि में आधे से अधिक था। वर्ष 2002-03 में आधे से कम होने के बाद यह वर्ष 2003-04 में दुबारा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पर हावी हो गया। लेकिन इस पैटर्न में 2004-05 और 2005-06 के अद्यतन दो वर्षों में निजी खपत की तुलना में निवेश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का मुख्य स्रोत होने के कारण

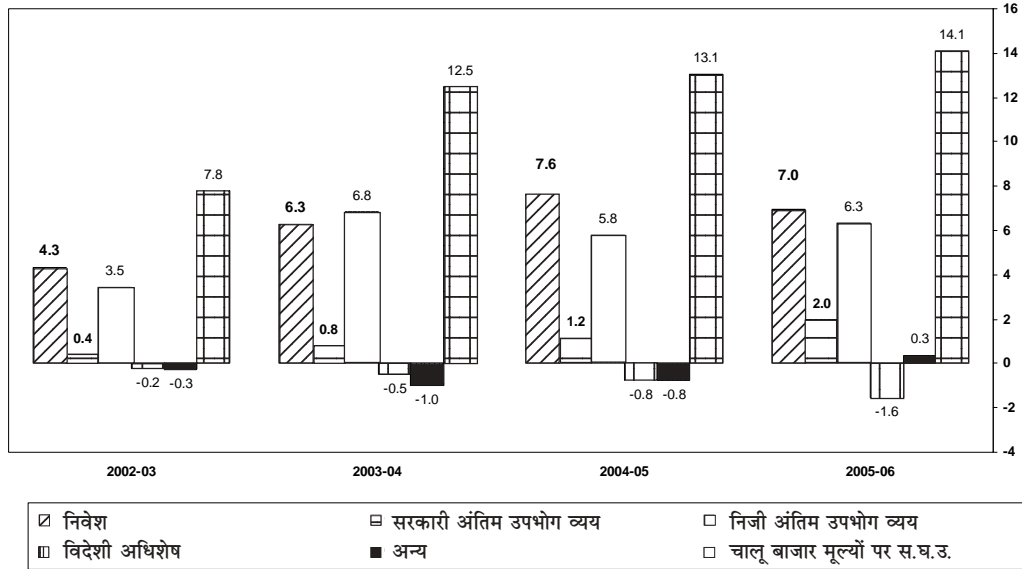
लाभकारी रूपान्तरण हुआ प्रतीत होता है (चित्र 1.2 और सारणी 1.5)। वर्ष 2004-05 तक के उपलब्ध राष्ट्रीय लेखा विवरणों में खपत और निवेश संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2004-05 में विद्यमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि में निवेश का 6.8 प्रतिशत बिन्दु योगदान हाल के वर्षों में पहली बार 6.1 प्रतिशत बिन्दु पर निजी अंतिम खपत व्यय के तदनुसूची योगदान से अधिक था। मांग पक्ष से चालू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के योगदान के संदर्भ में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान निवेश सतत रूप से अग्रणी रहा। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत के चालू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में निवेश के योगदान की प्रतिशतता क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत थी। निर्यात की तुलना में आयातों के तेजी से बढ़ने के साथ हाल के वर्षों में विदेशी अधिशेष का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सतत रूप से नकारात्मक योगदान बना हुआ है।

उत्पादन

1.41 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 5 फरवरी, 2007 को जारी फसल

चित्र 1.2

चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि में बिंदु योगदान



सारणी 1.5 : सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) का संघटन

(पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन)

	वर्तमान मूल्यों पर						1999-2000 मूल्यों पर					
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(क्यू)
कुल अंतिम उपभोग व्यय	6.7	8.5	5.0	10.2	9.5	11.7	1.7	5.9	1.7	6.2	5.7	7.4
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	5.0	6.3	3.3	6.6	10.3	18.1	-3.6	6.3	-0.4	2.5	5.4	9.8
निजी अंतिम उपभोग व्यय	7.1	8.9	5.4	10.9	9.4	10.6	2.8	5.8	2.1	6.9	5.7	7.0
सकल घरेलू पूंजी निर्माण	-0.3	3.3	19.0	24.9	27.3	22.1	-4.5	-1.8	16.6	19.1	19.0	16.5
जिसमें से												
सकल नियत पूंजी निर्माण	4.8	9.9	11.2	17.6	19.7	21.6	0.3	4.5	8.7	13.1	11.8	15.3
वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	22.1	4.5	22.3	14.7	39.5	27.4	18.2	5.7	21.8	5.8	28.1	22.0
घटाइए - वस्तुओं और सेवाओं का आयात	12.0	4.5	22.2	16.7	41.2	32.7	3.5	3.4	10.4	7.2	22.3	27.1
बाजार मूल्यों पर स.घ.उ.	7.7	8.5	7.8	12.5	13.1	14.1	4.0	5.2	3.7	8.4	8.3	9.2

क्यू : त्वरित पी : अनन्तिम
 स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2006-07 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 209.2 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो वर्ष 2005-06 में 208.6 मिलियन टन उत्पादन से मामूली अधिक है। गेहूं और दलहन के उत्पादन में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है। वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन काफी अधिक होने की प्रत्याशा है। कपास का 21.0 मिलियन गांठों का

प्रत्याशित उत्पादन वर्ष 2005-06 से न केवल 13.5 प्रतिशत अधिक है, बल्कि अब तक का सबसे अधिक भी है। इसी तरह से 315.5 मिलियन टन का गन्ने का प्रक्षेपित उत्पादन वर्ष 2005-06 में 270.0 मिलियन टन अनुमानित उत्पादन से 16.8 प्रतिशत अधिक है। मोटे अनाजों और तिलहनों का उत्पादन 2005-06 में उनके स्तरों की तुलना में क्रमशः 6.2 प्रतिशत और 15.7 प्रतिशत कम होने की संभावना है।

बागान फसलों (काँफी, चाय और रबड़); पशुधन और कुक्कुट उत्पाद; उद्यान उत्पाद; डेयरी और मात्स्यिकी के उत्पादन में सुधार होने की प्रत्याशा है।

1.42 फसलों, विशेषतया गेहू तथा दलहनों का उत्पादन अब कुछ समय से स्थिर है। गेहू उत्पादन 1999-2000 में 76.4 मिलियन टन के चरम स्तर पर पहुंच गया था जिसे पुनः हासिल नहीं किया जा सका है। दलहनों के मामले में, उत्पादन 1998-99 में तथा पुनः 2003-04 में 14.9 मिलियन टन पर पहुंच गया था किन्तु विगत तीन वर्षों में उस स्तर से काफी कम रहा, दालों के विविधीकरण में कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। यद्यपि दालों को 1990 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की परिधि में लाया गया तथा तिलहन, दलहन, आयल पॉम एवं मक्का (आई एस पी पी ओ एम) एकीकृत योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में अप्रैल, 2004 से यिान्वित किया जा रहा है, दालों का उत्पादन अवरुद्ध रहा है। चूंकि दालें जेनेटिव रूप से निम्न पैदावार वाली होती हैं, तथा उन्हें वर्षा पोषित दशाओं में सीमांत तथ्य उप-सीमांत भूमियों में उगाया जाता है, संकेन्द्रण को लघु सिंचाई, सूक्ष्म पोषक तत्वों, बेहतर उत्पादन पद्धतियों तथा परिष्कृत/बेहतर उत्पादक बीजों के विकास की ओर अंतरित किए जाने की आवश्यकता है। विदेशों में उपलब्धता सीमित होने के कारण दालों की कीमतों में कमी घरेलू उत्पादन की सुस्थिर वृद्धि पर निर्भर करेगी, गेहू के मामले में क्षेत्र विशिष्ट किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है जो जल प्रचुरता वाले पूर्वी प्रदेशों के लिए विशेषरूप से उपयुक्त हो।

1.43 वर्ष 2006-07 में विनिर्माण में न केवल सतत वृद्धि देखी गई बल्कि विद्युत क्षेत्र की वृद्धि में भी विशेष सुधार देखा गया। अप्रैल-दिसम्बर, 2006 के दौरान, वर्ष 2005 की इसी अवधि में हुई 9.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 11.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ विनिर्माण क्षेत्र ने आई आई पी के सन्दर्भ में मापी गई समग्र औद्योगिक वृद्धि का 91 प्रतिशत से अधिक योगदान था। विनिर्माण के क्षेत्र में रसायनों; मूल धातुओं; मशीनरी और उपस्कर एवं परिवहन उपस्कर का आई आई पी में 35.0 प्रतिशत भारांश के साथ इसकी वृद्धि में 55.2 योगदान दिया। ये सभी उद्योग कौशल-आधारित हैं और अपेक्षाकृत उच्च मूल्य-वर्धित उत्पादों का उत्पादन करते हैं। सूती वस्त्र और वस्त्र उत्पादों की वृद्धि भी दो अंकों में थी। तथापि खाद्य उत्पादों और चर्म के उप-सेक्टरों का कम

निष्पादन चिन्ता का विषय बना हुआ है। ये दोनों उद्योग न केवल स्थानीय संसाधन आधारित हैं; वरन रोजगार-परक भी हैं। प्रयोक्ता-आधारित वर्गीकरण की दृष्टि से वर्तमान वर्ष में, मूल वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में उच्चतर वृद्धि दरें देखी गईं। इन सेक्टरों के इन उच्चतर वृद्धि दरों को बनाए रखने की आशा है जैसा कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण के लगभग 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अतिरिक्त निवेश करने के उनके इरादों का संकेत दिया। खनन क्षेत्र में अप्रैल-दिसम्बर, 2005 में 0.4 प्रतिशत से अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि की बहाली के बावजूद इस क्षेत्र का निष्पादन औसत से कम बना हुआ है।

मानव विकास, निर्धनता और बेरोजगारी

1.44 सामाजिक क्षेत्र के विकास के प्रयासों का केन्द्र बिन्दु मानव विकास और सामाजिक आधारभूत ढांचे के सृजन के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र बने रहे। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा अधिदेशित सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में परिव्यय में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समग्र स्वास्थ्य रक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, समेकित बाल विकास सेवाएं, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शामिल हैं। उनकी कवरेज बढ़ाने के अतिरिक्त, कार्यान्वयन में उनकी पहुंच, वितरण और सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लेने के कठिन कार्य पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

1.45 सामाजिक आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के हाल के प्रयासों का महत्व यूएनडीपी की 2006 की विश्व मानव विकास रिपोर्ट में भारत की 2003 की अपेक्षा केवल एक स्थान ऊपर 2004 की 126वीं रैंक (177 में से) को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण III में यह उल्लेख किया गया है कि कैसे महिलाओं और बच्चों में व्यापक रूप से फैले अल्प-पोषण पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। देश में बुनियादी शिक्षा के संबंध में स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने भी 2007 की लक्षित तारीख तक सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा प्राप्त न कर पाने की सम्भावना और विद्यालयी प्रणाली से उत्तीर्ण हाने वाले बच्चों की उपलब्धि के निम्न स्तरों का उल्लेख किया है। सर्वशिक्षा

अभियान में बुनियादी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करने के अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.46 रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 2004-05 के दौरान विस्तृत पैमाने पर किए गए 61वें दौर के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम सुधारों के अंतर्गत बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि की गर्मागर्म बहस पर काफी प्रकाश डालते हैं। सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि कैसे रोजगार की वृद्धि दर, जो 1983-1994 के दौरान 2.1 प्रतिशत से घटकर 1993-2000 के दौरान 1.6 प्रतिशत रह गई थी, 1999-2005 के दौरान बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि रोजगार पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है, पर जनसांख्यिकी गतिशीलता और उच्च श्रम शक्ति भागीदारी के चलते बेरोजगारी की दर ('सामान्य प्रधान स्थिति' द्वारा यथामापित) में भी 1999-2000 के दौरान 2.8 प्रतिशत से 2004-05 के दौरान 3.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। यद्यपि सर्वेक्षण के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण अभी किया जाना है, तो भी कृषि की वृद्धि में मंदी का आना बेरोजगारी दर में वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक आंकड़ों संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1994 और 2004 के बीच संगठित क्षेत्र में रोजगार में चिन्ताजनक मामूली गिरावट ने अनुकूलतम विनियमन और प्रोत्साहनों के बारे में कुछ विचारणीय मुद्दे उठाए।

1.47 वर्ष 2004-05 के लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में एनएसएसओ के 61वें दौर के बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर, मिश्रित प्रत्यावर्तन (रिकाल) अवधि के संदर्भ में निर्धनता की स्थिति वर्ष 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत के स्तर से कम होकर वर्ष 2004-05 में लगभग 22 प्रतिशत रह गई है (पांच खाद्य-भिन्न मदों, नामतः कपड़ा, जूते, टिकाऊ सामान, शिक्षा और सांस्थानिक चिकित्सा व्यय के आंकड़े 365 दिवसीय प्रत्यावर्तन अवधि और शेष मदों के लिए उपभोक्ता आंकड़े 30 दिवसीय प्रत्यावर्तन अवधि से एकत्रित किए जाते हैं)। निर्धनता अनुपात में पांच प्रतिशत अंकों की गिरावट लाने के दसवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2005-07 में इस अनुपात में लगभग 1 प्रतिशत अंक की और गिरावट लाने की जरूरत है।

1.48 भारत वर्ष 2045 तक 'जनसांख्यिकी लाभ' से लाभ प्राप्त करता रहेगा। भारत 2.1 की कुल जनन क्षमता दर (जो महिला के अपने जीवनकाल के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या है) को प्राप्त कर लेगा जो वर्ष 2010 तक प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर है। पुनः जनन आयु समूह में जनसंख्या के उच्च अनुपात के चलते कुल जनसंख्या में वृद्धि वर्ष 2045 में जनसंख्या में स्थिरता से पूर्व, अगले 35 वर्षों तक जारी रहेगी। विकसित देशों के अनुभवों से पता चलता है कि प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने के बाद जनसंख्या में स्थिरता लाने में लगभग 35 वर्ष लगते हैं; यह केवल 35 वर्ष के बाद ही होता है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को प्रतिस्थापित करती है।

मुद्दे तथा प्राथमिकताएं

1.49 अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से उछाल आया है और यह संतुलित अभिवृद्धि की अवस्था से उच्च अभिवृद्धि के नए चरण की ओर अग्रसर हुई है। शिथिल वृद्धि से स्थायी उच्च अभिवृद्धि के पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक पलायन के तीव्रता हासिल करने के निमित्त दो मुद्दों और तीन प्राथमिकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ये दो मुद्दे हैं: संतुलित मुद्रास्फीति के साथ उच्च अभिवृद्धि कायम रखना; और ऐसी उच्च अभिवृद्धि का समावेशी स्वरूप। तीन प्राथमिकताएं हैं: उच्च अभिवृद्धि को कायम रखने और उसका प्रबंधन करने की चुनौती का सामना करना; अभिवृद्धि के दोहरे स्तम्भों नामतः राजकोषीय विवेक और उच्च निवेश को सुदृढ़ करना; और महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों की सहायता में सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावोत्पादकता में सुधार लाना।

1.50 उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में पड़े बिना उच्च अभिवृद्धि की निरन्तरता के प्रथम मुद्दे के संबंध में विभिन्न संकेतक सुझाते हैं कि वर्तमान अभिवृद्धि चरण को कायम रखा जा सकता है।

1.51 प्रथमतः, जनसांख्यिकीय लाभ के साथ उच्चतर अभिवृद्धि (कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या के बढ़ते अनुपात से) के परिणामस्वरूप अधिकाधिक निवेश को वित्तपोषित करने के लिए बचतों की दर में वृद्धि आने की संभावना है। वर्ष 2005-06 के लिए हाल ही में जारी बचत और निवेश आंकड़ों में पहले ही इस लाभकारी तथा पारस्परिक रूप से प्रबलकारी अभिवृद्धि बचत-अभिवृद्धि चक्र का साक्ष्य है।

1.52 दूसरे, वर्ष 1999-2000 से अर्थव्यवस्था में दक्षता सुधारों से उच्च अभिवृद्धि चरण में विश्वास संबलित होता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार अर्थव्यवस्था में अभिवर्धित सकल मूल्य के प्रति निवल पूंजी भंडार का अनुपात वर्ष 1999-2000 और 2004-05 के बीच 2.78 से घटकर 2.60 हो गया है। यद्यपि यह अनुपात वर्ष 2004-05 में बढ़कर 2.66 हो गया, यह वृद्धि मुख्यतः कृषि में अभिवर्धित मूल्य के प्रति निवल पूंजी भंडार के अनुपात में तदनुसूची वृद्धि के कारण थी। उद्योग में अभिवर्धित मूल्य के प्रति निवल पूंजी भंडार के अनुपात में उत्साहजनक और लगभग सुस्थिर गिरावट आयी है।

1.53 तीसरे, यह न केवल बचतों और निवेश में स्थायी अभिवृद्धि, उचित मजदूरी दरों पर श्रम की उपलब्धता और दक्षता वृद्धि अपितु पहले से ही सुविदित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के अतिरिक्त सेवाओं में नए अवसरों की उपलब्धता है जो नए उच्च वृद्धि चरण में विश्वास को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक उल्लेखनीय संक्रमण में, पर्यटन उद्योग ने विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में उत्साहजनक द्विअंकीय वार्षिक अभिवृद्धि दरें दर्शायी हैं। पर्यटन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और भारत में इसकी क्षमता देश के विशाल प्राकृतिक, मानव और प्रौद्योगिकीय संसाधनों के मद्देनजर सुविख्यात है। यह क्षेत्रक अपने पश्चवर्ती और अग्रवर्ती सम्पर्कों के जरिए अनेक अन्यो को विशेषतया होटलों, रेस्तरां और हस्तशिल्पों को प्रेरणा दे सकता है। यद्यपि राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) केवल 5.90 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, भारत पहले ही विश्व में सर्वाधिक तीव्र वृद्धिकारी पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। इसकी जैव-विविधता, विभिन्न प्रकार के अनोखे गंतव्य स्थानों और प्राकृतिक अवस्थलों को देखते हुए भारत नए उत्पादों यथा चिकित्सा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, सुस्वस्थता पर्यटन और बैठकों/ प्रोत्साहनों/अभिसर्यों एवं प्रदर्शनियों (एमआईसीई) के गंतव्य स्थल के रूप में भारत विपणन पर वर्धित महत्व के साथ अपने आप को वर्ष में 365 दिवसीय गंतव्यस्थल के रूप में रूपांतरित कर सकता है।

1.54 चौथे, इस विषय पर चिंता व्यक्त की गई है कि क्या देश अपनी वृद्धि क्षमता से अधिक विकास कर रहा है जिससे

इसकी श्रम शक्ति एवं पूंजी भंडार पर दबाव पड़ रहा है और इस प्रकार से मुद्रास्फीतिकारी अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत में बेरोजगारी, दृश्य और अदृश्य दोनों, के कारण अनावश्यक तेजी पर चिंताओं का संबंध क्षमता उपयोग और कौशल की कमियों से अधिक है। निवेशों के माध्यम से क्षमता अभिवर्धन में तीव्र वृद्धि क्षमता दबाव की समस्या को समाप्त कर सकती है। अत्यधिक तीव्रता का दूसरा संकेत अर्थात् पण्य वस्तुओं की आयात वृद्धि भी युक्तिसंगत सीमाओं के भीतर प्रतीत होती है।

1.55 पांचवां, आधारभूत संरचना जो वर्षों से अर्थव्यवस्था के वृद्धि निष्पादन को अवरूद्ध कर रही है, में सुधार आ रहा प्रतीत होता है। विद्युत, सड़क पत्तन और हवाई अड्डे जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति के लक्षण हैं। वैश्विक वित्तीय पूंजी को आकर्षित करने के लिए सड़क प्रदर्शनों (रोड शो) के बाद चार प्रमुख वित्तीय संस्थाओं (सिटीग्रुप, बाल्थस्टोन, अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम तथा भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी) द्वारा भारतीय अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए 15 फरवरी, 2007 को 5 बिलियन अमरीकी डालर की निधि की स्थापना एक उत्साहजनक घटनाक्रम है।

1.56 दूसरा मुद्दा *समावेशिता के संदर्भ में इस उच्च अभिवृद्धि स्वरूप के बारे में है।* अधिकाधिक लोगों को उत्पादक एवं स्थायी रोजगारों में लगाना समावेशी विकास का केन्द्र बिन्दु है। परन्तु ऐसी सफलता, मुख्यतः उच्च वृद्धि हासिल करने और उसे कायम रखने की सफलता पर निर्भर होगी। स्वयं वृद्धि के बिना समावेशी वृद्धि नहीं हो सकती है। पूर्वी एशिया का अनुभव स्पष्टतः दर्शाता है कि किस प्रकार उच्च अभिवृद्धि से गरीबी का उन्मूलन हो सकता है और विकासशील देश विकसित देश में रूपांतरित हो सकता है।

1.57 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन 61वें दौर के परिणाम स्पष्ट दर्शाते हैं कि किस प्रकार न केवल रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1993-2000 के दौरान 1.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2005 के दौरान 2.5 प्रतिशत हो गई अपितु यह वर्ष 1983-1994 के दौरान 2.1 प्रतिशत की दर को भी पार कर गई। बेरोजगारी में वृद्धि उच्च वृद्धि के कारण नहीं हुई है बल्कि इसलिए हुई है कि यह वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। इस मिथ्या परिकल्पना से बचना महत्वपूर्ण है कि समावेशी वृद्धि अनिवार्य रूप से निम्न वृद्धि होगी।

1.58 वृद्धि का समावेशी स्वरूप स्वयं ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भौतिक आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में की गई प्रगति द्वारा अनुकूल हो जाएगा। जब एक बालिका को शिक्षा के लाभों से वंचित किया जाता है तो वह बहुधा बड़ी होने पर अपने आपको विकास प्रक्रियाओं में सहभागिता से अलग रखती है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं, जब उनके गांव को सम्पर्कता का लाभ नहीं मिलता, चाहे वह सड़के, बिजली या संचार ही क्यों न हो।

1.59 प्राथमिकताओं में प्रधान प्राथमिकता उच्च अभिवृद्धि को कायम रखने और उसके प्रबंधन की चुनौती का सामना करना है। चरण संक्रमण से अपरिहार्य रूप से नई समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसके लिए मानसिक स्थिति, आर्थिक आचरण और नीति निर्माण में अपेक्षित समायोजन करना अनिवार्य है। उच्च अभिवृद्धि के बारे में चिन्तित होने की कोई गुंजाईश नहीं है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्व एशियाई “करिश्मा” के पश्चात हाल ही में चीन में और भी अधिक तीव्र अभिवृद्धि हुई है। भारत में विकास की गति को बढ़ाना शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है।

1.60 हाल के समय के मुद्रास्फीति विश्वभर में प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धि से प्रेरित रही है। भारत में, खाद्य की अनिवार्य मदों की कीमतें दबाव में हैं। क्यों? क्योंकि आपूर्ति पक्ष कमजोर है और उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच मध्यस्थता कमजोर और अकुशल है। मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए विशेषकर कृषि क्षेत्र में आपूर्ति से संबंधित नीतियां बहुत महत्व रखती हैं। ऐसी नीतियां न सिर्फ मुद्रास्फीति का सामना करने में मदद करेंगी बल्कि विकास को भी बढ़ावा देंगी। यह ध्यान दिया जाना जरूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव यह दिखाता है कि यह जरूरी नहीं कि अनुकूल उच्च वृद्धि की कीमत परेशान करने वाली मुद्रास्फीति के रूप में चुकानी पड़े। मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई को चरणबद्ध रूप में लड़ा जाना होगा ताकि नीतियां विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुद्रास्फीति को काबू में रख सकें। उपयुक्त नीतियों के चलते मुद्रास्फीति के बिना उच्च वृद्धि को बनाए रखना तथा उसका प्रबंध करना संभव होना चाहिए।

1.61 वस्तु-विशेष की आपूर्ति की कमी से प्रेरित हुई मुद्रास्फीति के तात्कालिक समाधान ढूंढना कठिन हो सकता है। मुद्रास्फीति की ऐसी समस्या का स्थायी समाधान दालों, खाद्य तेलों, चावल एवं गेहूं जैसे उत्पादों की बढ़ती उपज और घरेलू उत्पादन में ढूंढा जाना होगा। प्रौद्योगिकी के प्रसार के जरिए उपज के स्तर को बढ़ाने की जबर्दस्त गुंजाईश है।

साथ ही साथ, यह स्वीकारने की भी जरूरत है कि अल्पावधि में किसान के लिए “लाभकारी” मूल्य और उपभोक्ता के लिए “उचित” मूल्य के बीच संभावित अंतर्विरोध है। यही अंतर्विरोध पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के मामले में भी उठ खड़े होते हैं। ऐसे अन्तर्विरोध का अल्पावधिक समाधान राजकोषीय औचित्य को मुश्किल में डालकर नहीं किया जाना चाहिए।

1.62 दूसरी प्राथमिकता है उच्च वृद्धि के दो स्तंभों अर्थात् राजकोषीय विवेक और उच्च निवेश को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था में देखी गई वृद्धि का पुनरुत्थान कोई इतफाक नहीं बल्कि उचित नीतियों तथा अनेक सुधार उपायों का परिणाम है। गत कुछ वर्षों के अनुभव ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय विवेक के लाभों को साफ-साफ दर्शाया है। उच्च वृद्धि के साथ-साथ किए गए सुधारों के कारण पिछले कुछ वर्षों में निवेश में उछाल आया है। जहां वृद्धि और जनसांख्यिकी लाभांश में आई तेजी बचत को और इस तरह निवेश को साथ-ही-साथ बढ़ावा देती रहेगी, अर्थव्यवस्था में निवेशों में वृद्धि करने के लिए नीतियां लचीले तरीके से इस प्रकार तैयार की जानी होंगी कि वृद्धि की मजबूत बुनियाद डाली जा सके। सरकारी और निजी, घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश की जरूरत है। परन्तु सरकारी निवेश बढ़ाने की उत्सुकता में राजकोषीय अपव्यय के लालच को रोकना महत्वपूर्ण है। राजकोषीय औचित्य का अनुसरण करना कभी भी किसी देश में आसान नहीं रहा है। पहाड़ी पर चढ़ने की तरह ज्यों-ज्यों गंतव्य नजदीक आता जाता है समायोजन कठिन होते जाते हैं। भारत की निवेश ग्रेड सार्वभौम रेटिंग सिर्फ स्पष्ट सुदृढ़ आर्थिक संभावनाओं, इसके भुगतान संतुलन की शक्ति और पूंजी बाजारों को ही प्रतिबिंबित नहीं करती बल्कि इसकी सुधरी हुई स्थिति को भी प्रतिबिंबित करती है।

1.63 तीसरी प्राथमिकता महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की कारगरता में सुधार करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतमंदों को सहायता के क्षेत्रों में प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप से सम्मिलित अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। परिणामों पर बल देते हुए और सरकारी सामान और सेवाओं के सुपुर्दगी तंत्र में किसी अपव्यय अथवा हेरीफेरी को रोकते हुए खर्च किए गए प्रत्येक कर-रुपये का मूल्य सुनिश्चित किया जाना होगा। इस संबंध में कार्यक्रमों को मानीटर लगाया जाना उपयुक्त रूप से बनाया जाना और कार्यक्रमों महत्वपूर्ण है।

1.64 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों में स्व रोजगार अवसरों को पैदा करने की दो वैकल्पिक योजनाओं, नामशः प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा स्व सहायता समूह-बैंक संयोजन, की तुलना कार्यक्रम की परिकल्पना के महत्व को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वसूली 2005 को समाप्त तीन वर्षों में लगभग 35 प्रतिशत रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण गरीबों के स्व सहायता समूह को बैंकिंग प्रणाली (स्व सहायता समूह बैंक संयोजन) से जोड़ने के कार्यक्रम को 1992 में नाबार्ड के माध्यम से प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और इसे 1996 में मुख्यधारा में लाया गया। स्व सहायता समूह बैंक-संयोजन मुख्यतः छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि और गैर-कृषि मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों पर केन्द्रित है। इस कार्यक्रम की खासियत शून्य सब्सिडी है। सूचना मिली है कि स्व सहायता समूह बैंक संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वसूली दरें 90 प्रतिशत के आसपास हैं। इस विषयता के परिणाम स्पष्ट हैं। अल्प वसूली के ऋण कार्यक्रम का हश्र निश्चित रूप से असफलता में होगा।

1.65 सामाजिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए मात्र क्षेत्र या कार्यक्रमों की संख्या का विस्तार पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आरम्भ से, जिसमें देश के लिए एक संभाव्य सामाजिक सुरक्षा जाल की व्यवस्था की गई है, अनेकानेक गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन समावेशिता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसे गरीबी को कम करना होगा तथा ग्रामीण अवसंरचना में सुधार लाना होगा; तथा ऐसा करने में कोई भी विफलता इसके प्रभावहीन क्रियान्वयन का संकेतक होगी।

1.66 सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सभी सामाजिक क्षेत्रक कार्यक्रमों के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता है। हालांकि काफी अधिक संख्या में विद्यालयी बच्चों का नामांकन अभी प्राइमरी विद्यालयों में कराया जाना शेष है, एक स्वतंत्र सर्वेक्षण से यह उद्घटित हुआ है कि अनेक विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक वह सब कुछ सीखते हैं जो

उन्हें दूसरी कक्षा में सीख लेना चाहिए। तथापि, देश के विभिन्न भागों में सफलता की कहानियां भी हैं जिन्हें अभी दोहराया जाना है।

1.67 सब्सिडियां बाजार विफलताओं विशेषतया भोजन जैसी मूलभूत अनिवार्य वस्तुओं की अल्प खपत में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण राजकोषीय नीतिगत साधन हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, अनुमानतः 150 मिलियन अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता के साथ इस प्रणाली के समक्ष नई चुनौतियां आएंगी। ऐसी चुनौतियों में बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली के साथ-साथ आहार संबंधी पद्धतियों में परिवर्तन करने की चुनौती भी शामिल होगी। सभी सब्सिडियों को विशेषकर गरीबों तथा छोटे एवं सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और शहरी निर्धनों जैसे वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचाने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधिदेश को अभी कार्यान्वित किया जाना बाकी है। सब्सिडी से जुड़ी अनिर्णायक बहस दोबारा शुरू किए जाने की जरूरत है और वास्तव में ही जरूरतमंद लोगों को लागत-प्रभावी आय का अंतरण किए जाने की प्रक्रिया में ठोस प्रगति किए जाने की आवश्यकता है। सब्सिडियों के वितरण के लिए वैकल्पिक पद्धतियां मौजूद हैं। कम से कम उनका प्रायोगिक आधार पर परीक्षण अवश्य किया जाए और इस अनुभव से एक वैकल्पिक और अधिक कारगर पद्धति की खोज की जाए।

1.68 मौजूदा आर्थिक स्थिति की विशेषता है इससे जुड़ा आशावाद। विकास की गति को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे विकास का स्थायित्व वृद्धि को मद्धिम किए बिना मुद्रास्फीति को काबू में करने की सावधानीपूर्वक बनाई गई चरणबद्ध नीतियों पर; विशेषकर कृषि में आपूर्ति संबंधी उपयुक्त उपाय करने पर; शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसी सामाजिक सेवाओं को अधिक समावेशी बनाने के लिए उनके बेहतर निर्माण और उनकी अधिक कारगर सुपुर्दगी पर; और बुनियादी ढांचे में नई जान डालने पर निर्भर करेगा। वैश्विक बृहत-आर्थिक असंतुलनों के तेजी से बढ़ने के नकारात्मक जोखिम, तेल की अस्थिर कीमतें और दोहा-दौर के समापन में होने वाले विलम्ब अभी बरकरार है, लेकिन अब इनका स्वरूप सीमित प्रतीत हो रहा है।